

EXAM GENIUS

Presents

WEEKLY GENIUS BANKING AND FINANCE

In BILINGUAL

26 APR - 2 MAY 2026

India's No. 1 Platform for UPSC
| SSC | BANK RAILWAY Exam



 UPSC

 SSC

 BANK

 RAILWAY

 STATE EXAMS

Ques: RBI imposed a ₹41.8 lakh penalty on which bank for KYC-related violations?

प्रश्न: KYC से संबंधित उल्लंघनों के लिए RBI ने ₹41.8 लाख का जुर्माना किस बैंक पर लगाया?

- A) Bandhan Bank / बंधन बैंक
- B) HDFC Bank / एचडीएफसी बैंक
- C) SBI / भारतीय स्टेट बैंक
- D) ICICI Bank / आईसीआईसीआई बैंक
- E) Axis Bank / एक्सिस बैंक

Answer: Option A

Explanation | व्याख्या:

- The Reserve Bank of India imposed a ₹41.8 lakh penalty on Bandhan Bank for non-compliance with KYC norms.
- Reserve Bank of India ने KYC नियमों के उल्लंघन के लिए Bandhan Bank पर ₹41.8 लाख का जुर्माना लगाया।
- The violations included failure to comply with Know Your Customer (KYC) guidelines.
- इसमें KYC (नो योर कस्टमर) दिशानिर्देशों का पालन न करना शामिल था।
- The bank also did not conduct periodic reviews of risk categorisation of accounts and sanctioned director-related loans.
- बैंक ने खातों के जोखिम वर्गीकरण की समय-समय पर समीक्षा नहीं की और डायरेक्टर से संबंधित ऋण भी स्वीकृत किए।
- Additionally, RBI imposed a ₹80,000 penalty on Muthoot Housing Finance Company for violating Fair Practice Code norms.
- इसके अलावा, RBI ने Muthoot Housing Finance Company पर ₹80,000 का जुर्माना लगाया।
- These actions highlight the importance of strict compliance with banking regulations.
- ये कदम बैंकिंग नियमों के सख्त पालन के महत्व को दर्शाते हैं।

Static Part | स्थैतिक जानकारी:

- RBI Established – 1935
- आरबीआई की स्थापना – 1935
- Headquarters – Mumbai
- मुख्यालय – मुंबई
- Governor – Sanjay Malhotra
- गवर्नर – Sanjay Malhotra
- Function – Regulator of Banking System
- कार्य – बैंकिंग प्रणाली का नियामक

Ques: For how many years has B Ramesh Babu been re-appointed as MD & CEO of Karur Vysya Bank?

प्रश्न: बी रमेश बाबू को करूर वैश्य बैंक के MD & CEO के रूप में कितने वर्षों के लिए पुनः नियुक्त किया गया है?

- A) 1 year / 1 वर्ष
- B) 2 years / 2 वर्ष
- C) 3 years / 3 वर्ष
- D) 4 years / 4 वर्ष
- E) 5 years / 5 वर्ष

Answer: Option B

Explanation | व्याख्या:

- The Reserve Bank of India (RBI) approved the re-appointment of B Ramesh Babu.
- भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने बी रमेश बाबू की पुनर्नियुक्ति को मंजूरी दी।
- He will continue as MD & CEO of Karur Vysya Bank.

- वह करूर वैश्य बैंक के MD & CEO के रूप में कार्य करते रहेंगे।
- This is his third term in the position.
- यह उनका तीसरा कार्यकाल है।
- The tenure is for 2 years.
- यह कार्यकाल 2 वर्षों का होगा।
- The new term will be effective from July 29, 2026.
- नया कार्यकाल 29 जुलाई 2026 से प्रभावी होगा।
- RBI approved the re-appointment on April 24, 2026.
- RBI ने यह मंजूरी 24 अप्रैल 2026 को दी।
- The announcement was made to stock exchanges by the bank.
- बैंक द्वारा इसकी घोषणा स्टॉक एक्सचेंजों को की गई।

Static Part | स्थैतिक जानकारी:

- RBI – Reserve Bank of India
- RBI – भारतीय रिज़र्व बैंक
- Established – 1 April 1935
- स्थापना – 1 अप्रैल 1935
- Headquarters – Mumbai
- मुख्यालय – मुंबई
- Governor – Sanjay Malhotra
- गवर्नर – संजय मल्होत्रा
- Karur Vysya Bank – Founded 1916
- करूर वैश्य बैंक – स्थापना 1916
- Headquarters – Karur, Tamil Nadu
- मुख्यालय – करूर, तमिलनाडु

Ques: RBI cancelled the licence of Paytm Payments Bank under which Act?
प्रश्न: आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक का लाइसेंस किस अधिनियम के तहत रद्द किया?

- A) RBI Act, 1934 / आरबीआई अधिनियम, 1934
- B) Banking Regulation Act, 1949 / बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949
- C) Companies Act, 2013 / कंपनी अधिनियम, 2013
- D) FEMA, 1999 / फेमा, 1999
- E) Payment and Settlement Systems Act, 2007 / भुगतान एवं निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007

Answer: Option B

Explanation | व्याख्या:

- The Reserve Bank of India (RBI) cancelled the banking licence of Paytm Payments Bank Limited (PPBL) on April 24, 2026.
- भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने 24 अप्रैल 2026 को पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड (PPBL) का बैंकिंग लाइसेंस रद्द कर दिया।
- The action was taken under Section 22(4) of the Banking Regulation Act, 1949.
- यह कार्रवाई बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 22(4) के तहत की गई।
- The bank was found non-compliant with licensing conditions and regulatory norms.
- बैंक को लाइसेंस की शर्तों और नियामकीय मानकों का पालन न करने वाला पाया गया।
- PPBL is now prohibited from conducting banking business.
- अब PPBL को बैंकिंग व्यवसाय करने से रोक दिया गया है।
- RBI will initiate the process for winding up of the bank.
- आरबीआई बैंक को बंद करने (वाइंडिंग अप) की प्रक्रिया शुरू करेगा।

Static Part | स्थैतिक जानकारी:

- RBI Established – 1935
- आरबीआई की स्थापना – 1935
- Headquarters – Mumbai
- मुख्यालय – मुंबई

- Governor – Sanjay Malhotra
 - गवर्नर – संजय मल्होत्रा
 - Banking Regulation Act – 1949
 - बैंकिंग विनियमन अधिनियम – 1949
-

Ques: What initiative was launched by FM Nirmala Sitharaman on SEBI's 38th Foundation Day?

प्रश्न: SEBI के 38वें स्थापना दिवस पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कौन-सी पहल लॉन्च की?

- A) Mission Suraksha / मिशन सुरक्षा
- B) Mission Vikas / मिशन विकास
- C) Mission Jagrook / मिशन जागरूक
- D) Mission Nivesh / मिशन निवेश
- E) Mission Digital / मिशन डिजिटल

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

- Union Finance Minister Smt. Nirmala Sitharaman delivered the keynote address at SEBI's 38th Foundation Day in Mumbai.
- केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने मुंबई में SEBI के 38वें स्थापना दिवस को संबोधित किया।
- She launched SEBI's nationwide investor awareness initiative "Mission Jagrook".
- उन्होंने SEBI की देशव्यापी निवेशक जागरूकता पहल "मिशन जागरूक" लॉन्च की।
- She highlighted cybersecurity as the most pressing challenge for financial markets.
- उन्होंने साइबर सुरक्षा को वित्तीय बाजारों के लिए सबसे बड़ी चुनौती बताया।
- A single major cyberattack can disrupt markets, erode wealth, and reduce public trust.

- एक बड़ा साइबर हमला बाजारों को बाधित कर सकता है, संपत्ति को नुकसान पहुंचा सकता है और भरोसा कम कर सकता है।
- AI-led tools are making cyberattacks more adaptive, scalable, and autonomous.
- AI आधारित उपकरण साइबर हमलों को अधिक अनुकूल, स्केलेबल और स्वचालित बना रहे हैं।
- Threats include system vulnerabilities, supply chain attacks, and real-time coordinated intrusions.
- खतरों में सिस्टम कमजोरियां, सप्लाई चेन हमले और रियल-टाइम समन्वित हमले शामिल हैं।
- SEBI's Cybersecurity & Cyber Resilience Framework (April 2025) provides a strong base.
- SEBI का साइबर सुरक्षा और साइबर रेजिलिएंस फ्रेमवर्क (अप्रैल 2025) एक मजबूत आधार प्रदान करता है।
- SEBI's Data Analytics & Digital Forensics Lab uses AI/ML models to detect frauds.
- SEBI की डेटा एनालिटिक्स और डिजिटल फॉरेंसिक लैब AI/ML मॉडल से धोखाधड़ी का पता लगाती है।
- She praised "SEBI Check", which helps investors verify payment details of intermediaries.
- उन्होंने "SEBI Check" की सराहना की, जो निवेशकों को मध्यस्थों के भुगतान विवरण सत्यापित करने में मदद करता है।
- She raised concern over fake investment apps/videos using deepfake AI on social media.
- उन्होंने सोशल मीडिया पर डीपफेक AI से बने फर्जी निवेश ऐप/वीडियो पर चिंता जताई।
- Emphasised need for public awareness campaigns and rapid takedown mechanisms.
- जन जागरूकता अभियान और त्वरित हटाने की व्यवस्था की आवश्यकता पर जोर दिया।
- Advocated soft-touch regulation and public consultation for better governance.
- बेहतर शासन के लिए सॉफ्ट-टच रेगुलेशन और जन परामर्श की वकालत की।
- Public consultation was proposed in Union Budget 2023 for regulatory

improvement.

- केंद्रीय बजट 2023 में नियामकीय सुधार के लिए जन परामर्श का प्रस्ताव दिया गया था।

Ques: India extended a ₹3,000 crore currency swap facility to which country under the SAARC Currency Swap Framework 2024–27?

प्रश्न: भारत ने सार्क करेंसी स्वैप फ्रेमवर्क 2024–27 के तहत ₹3,000 करोड़ की करेंसी स्वैप सुविधा किस देश को प्रदान की है?

- A) Sri Lanka / श्रीलंका
- B) Nepal / नेपाल
- C) Bangladesh / बांग्लादेश
- D) Maldives / मालदीव
- E) Bhutan / भूटान

Answer: Option D

Explanation | व्याख्या:

- India has approved a ₹3,000 crore currency swap facility for Maldives under the SAARC Currency Swap Framework 2024–27.
- भारत ने सार्क करेंसी स्वैप फ्रेमवर्क 2024–27 के तहत Maldives के लिए ₹3,000 करोड़ की करेंसी स्वैप सुविधा मंजूर की है।
- The facility has been extended through the INR Swap Window of the framework.
- यह सुविधा फ्रेमवर्क के INR स्वैप विंडो के माध्यम से दी गई है।
- The agreement was signed between the Reserve Bank of India and the Maldives Monetary Authority.
- यह समझौता Reserve Bank of India और Maldives Monetary Authority के बीच हुआ।
- Maldives also repaid a \$400 million swap facility availed in October 2024.

- मालदीव ने अक्टूबर 2024 में ली गई \$400 मिलियन स्वैप सुविधा भी वापस कर दी।
- The framework (2024–27) includes a separate INR Swap Window with a total corpus of ₹250 billion.
- 2024–27 फ्रेमवर्क में ₹250 बिलियन का अलग INR स्वैप विंडो शामिल है।
- RBI also provides swap arrangements in US Dollar and Euro with a corpus of \$2 billion.
- RBI अमेरिकी डॉलर और यूरो में भी \$2 बिलियन की स्वैप सुविधा प्रदान करता है।

Static Part | स्थैतिक जानकारी:

- SAARC Established – 8 December 1985
- SAARC की स्थापना – 8 दिसंबर 1985
- Headquarters – Kathmandu
- मुख्यालय – Kathmandu
- SAARC Members: Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, India, Maldives, Nepal, Pakistan, Sri Lanka
- सार्क सदस्य: अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका
- Currency Swap – Arrangement between central banks to exchange currencies
- करेंसी स्वैप – केंद्रीय बैंकों के बीच मुद्रा विनिमय की व्यवस्था

Ques: The BSE Housing Finance Index is derived from which broader index?

प्रश्न: BSE हाउसिंग फाइनेंस इंडेक्स किस व्यापक इंडेक्स से लिया गया है?

- A) BSE Sensex / बीएसई सेंसेक्स
- B) Nifty 50 / निफ्टी 50
- C) BSE 500 / बीएसई 500
- D) BSE 1000 / बीएसई 1000
- E) Nifty Bank / निफ्टी बैंक

Answer: Option D

Explanation | व्याख्या:

- The BSE Housing Finance Index has been launched by BSE Index Services.
- BSE Housing Finance Index को BSE Index Services द्वारा लॉन्च किया गया है।
- It is derived from the BSE 1000 Index.
- यह BSE 1000 Index से लिया गया है।
- It tracks the performance of companies engaged in housing finance and home loans.
- यह हाउसिंग फाइनेंस और होम लोन से जुड़ी कंपनियों के प्रदर्शन को ट्रैक करता है।
- The index consists of 11 stocks from the housing finance sector.
- इस इंडेक्स में हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर की 11 कंपनियां शामिल हैं।
- Base Date – 22 June 2015 | Base Value – 1000
- आधार तिथि – 22 जून 2015 | आधार मान – 1000
- It is reconstituted semi-annually (June and December).
- इसे साल में दो बार (जून और दिसंबर) पुनर्गठित किया जाता है।
- Top constituent: LIC Housing Finance (~17.16% weight).
- शीर्ष घटक: LIC Housing Finance (~17.16% भार)।
- PNB Housing Finance Ltd.: 16.56%
- Sammaan Capital Ltd.: 14.16%
- Home First Finance Company: 9.55%
- Bajaj Housing Finance Ltd.: 9.24%
- Aptus Value Housing Finance: 8.65%
- Can Fin Homes Ltd.: 8.51%
- [Redacted] Housing Finance Ltd.: 5.70%
- AAVAS Financiers Ltd.: 4.98%
- India Shelter Finance Corp.: 3.89% (Lowest weight)

Ques: The Reserve Bank of India (RBI) imposed a total penalty of ₹2.60 lakh on banks and a payment firm in 2026 due to which reason?

प्रश्न: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने 2026 में बैंकों और एक पेमेंट फर्म पर ₹2.60 लाख का कुल जुर्माना किस कारण लगाया?

- A) Fraud and cyber attack / धोखाधड़ी और साइबर हमला
B) Non-compliance with regulatory directions / नियामकीय निर्देशों का पालन न करना
C) Tax evasion / कर चोरी
D) Money laundering / मनी लॉन्ड्रिंग
E) Loan default / ऋण चूक

Answer: Option B

Explanation | व्याख्या:

- The Reserve Bank of India imposed a total penalty of ₹2.60 lakh.
- भारतीय रिजर्व बैंक ने कुल ₹2.60 लाख का जुर्माना लगाया।
- The reason was non-compliance with regulatory directions.
- इसका कारण नियामकीय निर्देशों का पालन न करना था।
- Entities penalised include Hardoi Jilla Sahkari Bank Ltd (₹1 lakh).
- दंडित संस्थाओं में Hardoi Jilla Sahkari Bank Ltd (₹1 लाख) शामिल है।
- Dr Babasaheb Ambedkar Nagari Sahakari Bank Ltd (₹80,000) was also penalised.
- Dr Babasaheb Ambedkar Nagari Sahakari Bank Ltd (₹80,000) पर भी जुर्माना लगाया गया।
- Ebix Payment Services Pvt Ltd (₹80,000) was the third entity penalised.
- Ebix Payment Services Pvt Ltd (₹80,000) तीसरी दंडित संस्था थी।
- Hardoi Jilla Sahkari Bank violated KYC guidelines and failed to review risk categorisation of accounts.
- Hardoi Jilla Sahkari Bank ने KYC दिशानिर्देशों का उल्लंघन किया और खातों के जोखिम वर्गीकरण की समीक्षा नहीं की।
- Dr Babasaheb Ambedkar Nagari Sahakari Bank violated exposure norms, UCB restrictions, and SAF rules.
- Dr Babasaheb Ambedkar Nagari Sahakari Bank ने एक्सपोजर मानदंड, UCB प्रतिबंध और SAF नियमों का उल्लंघन किया।
- Ebix Payment Services failed to properly categorise customer risk.

- Ebix Payment Services ग्राहक जोखिम का सही वर्गीकरण करने में विफल रहा।

Ques: GIFT City has granted its first family office permit to which company?
प्रश्न: गिफ्ट सिटी ने अपना पहला फैमिली ऑफिस परमिट किस कंपनी को दिया है?

- A) Aditya Birla Capital / आदित्य बिड़ला कैपिटल
- B) Poornam Asset Management IFSC Pvt Ltd / पूर्णम एसेट मैनेजमेंट IFSC प्राइवेट लिमिटेड
- C) HDFC Asset Management / एचडीएफसी एसेट मैनेजमेंट
- D) ICICI Prudential AMC / आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी
- E) SBI Capital Markets / एसबीआई कैपिटल मार्केट्स

Answer: Option B

Explanation | व्याख्या:

- Gujarat International Finance Tec-City (GIFT City) has issued its first license for a family investment fund.
- Gujarat International Finance Tec-City (गिफ्ट सिटी) ने पहला फैमिली इन्वेस्टमेंट फंड लाइसेंस जारी किया।
- The permit was granted to Poornam Asset Management IFSC Pvt Ltd.
- यह परमिट Poornam Asset Management IFSC Pvt Ltd को दिया गया है।
- It marks a major step in managing private wealth within India's financial hub.
- यह भारत के वित्तीय हब में प्राइवेट वेल्थ मैनेजमेंट की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।
- The move aims to build a globally competitive ecosystem for family offices.
- this पहल का उद्देश्य फैमिली ऑफिस के लिए वैश्विक प्रतिस्पर्धी इकोसिस्टम बनाना है।
- GIFT City offers a flexible regulatory environment to attract global investors.
- गिफ्ट सिटी वैश्विक निवेशकों को आकर्षित करने के लिए लचीला नियामक वातावरण प्रदान करता है।
- It is expected to position India as an alternative to global financial hubs like

Dubai.

• इससे भारत को दुबई जैसे वैश्विक वित्तीय केंद्रों के विकल्प के रूप में स्थापित करने में मदद मिलेगी।

Ques: NPCI Bharat Bill Pay Limited (NBBL) onboarded which insurance service as a biller on the Bharat Connect platform?

प्रश्न: NPCI भारत बिल पे लिमिटेड (NBBL) ने भारत कनेक्ट प्लेटफॉर्म पर किस बीमा सेवा को बिलर के रूप में जोड़ा?

- A) LIC / एलआईसी
- B) Postal Life Insurance (PLI) / पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस
- C) HDFC Life / एचडीएफसी लाइफ
- D) ICICI Prudential / आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल
- E) SBI Life / एसबीआई लाइफ

Answer: Option B

Explanation | व्याख्या:

- NPCI Bharat Bill Pay Limited (NBBL), a subsidiary of National Payments Corporation of India, onboarded Postal Life Insurance (PLI) as a biller under the insurance category on Bharat Connect.
- NPCI Bharat Bill Pay Limited (NBBL), जो National Payments Corporation of India की सहायक कंपनी है, ने Postal Life Insurance (PLI) को भारत कनेक्ट पर बीमा श्रेणी में बिलर के रूप में जोड़ा।
- With this addition, the number of insurance billers increased to 65.
- इस जुड़ाव के बाद बीमा बिलर्स की संख्या बढ़कर 65 हो गई।
- The platform now supports over 22,640 billers across 29 categories.
- प्लेटफॉर्म अब 29 श्रेणियों में 22,640 से अधिक बिलर्स को सपोर्ट करता है।
- Policyholders of Postal Life Insurance and Rural Postal Life Insurance can pay premiums through digital platforms and offline agents.

- Postal Life Insurance और Rural Postal Life Insurance के पॉलिसीधारक अब डिजिटल प्लेटफॉर्म और ऑफलाइन एजेंट्स के माध्यम से प्रीमियम जमा कर सकते हैं।
- State Bank of India acted as the Biller Operating Unit (BOU).
- State Bank of India ने Biller Operating Unit (BOU) के रूप में कार्य किया।
- Postal Life Insurance is operated by India Post under the Department of Posts, Ministry of Communications.
- Postal Life Insurance का संचालन India Post द्वारा किया जाता है, जो Department of Posts, संचार मंत्रालय के अंतर्गत आता है।

About NBBL :

- Established : 2021
- HQ : Mumbai
- MD & CEO : Noopur Chaturvedi

Ques: SBI aims to expand its balance sheet to what percentage of India's GDP by 2030?

प्रश्न: एसबीआई 2030 तक अपनी बैलेंस शीट को भारत के GDP के कितने प्रतिशत तक बढ़ाना चाहता है?

- A) 15%
- B) 20%
- C) 25%
- D) 30%
- E) 35%

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

- State Bank of India aims to expand its balance sheet to 25% of India's GDP by 2030.
- स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का लक्ष्य 2030 तक अपनी बैलेंस शीट को भारत के GDP के

25% तक बढ़ाना है।

- The target is part of its long-term SBS 2030 (Sustain, Build, Scale) strategy.
- यह लक्ष्य इसकी दीर्घकालिक SBS 2030 (Sustain, Build, Scale) रणनीति का हिस्सा है।
- Currently, SBI's balance sheet is around 20% of India's GDP.
- वर्तमान में एसबीआई की बैलेंस शीट लगभग भारत के GDP का 20% है।
- The bank follows a bottom-up approach, focusing on growth in 800 districts.
- बैंक बॉटम-अप अप्रोच अपनाते हुए 800 जिलों में विकास पर ध्यान दे रहा है।
- It aims to increase market share by 1% in each district.
- इसका लक्ष्य प्रत्येक जिले में 1% मार्केट शेयर बढ़ाना है।
- SBI plans to double its balance sheet every 6 years.
- एसबीआई हर 6 वर्षों में अपनी बैलेंस शीट दोगुनी करने की योजना बना रहा है।
- Focus areas include RAM sector (Retail, Agriculture, MSME) and corporate lending.
- फोकस क्षेत्र में RAM सेक्टर (रिटेल, कृषि, MSME) और कॉर्पोरेट लेंडिंग शामिल हैं।
- The bank is pushing digital transformation via YONO 2.0 and service expansion.
- बैंक YONO 2.0 और सेवा विस्तार के माध्यम से डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन पर जोर दे रहा है।
- SBI aims to improve its global ranking among top banks.
- एसबीआई का लक्ष्य वैश्विक स्तर पर शीर्ष बैंकों में अपनी रैंकिंग सुधारना है।

Static Part | स्थैतिक जानकारी:

- SBI Foundation Day – 1 July 1955
 - एसबीआई स्थापना दिवस – 1 जुलाई 1955
 - Headquarters – Mumbai
 - मुख्यालय – मुंबई
 - Chairman – Challa Sreenivasulu Setty
 - अध्यक्ष – चल्ला श्रीनिवासुलु सेट्टी
 - Tagline – Pure Banking Nothing Else
 - टैगलाइन – Pure Banking Nothing Else
-

Ques: According to NSSO data (April 2026), which area in India has higher health insurance coverage as of 2025?

प्रश्न: NSSO (अप्रैल 2026) के अनुसार 2025 तक भारत में किस क्षेत्र में स्वास्थ्य बीमा कवरेज अधिक है?

- A) Urban areas / शहरी क्षेत्र
- B) Rural areas / ग्रामीण क्षेत्र
- C) Both equal / दोनों समान
- D) Only metropolitan cities / केवल महानगर
- E) None of the above / उपरोक्त में से कोई नहीं

Answer: Option B

Explanation | व्याख्या:

- According to NSSO data (April 2026), health insurance coverage in India has increased significantly over the past eight years.
- NSSO (अप्रैल 2026) के अनुसार पिछले आठ वर्षों में भारत में स्वास्थ्य बीमा कवरेज में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।
- As of 2025, rural coverage (47.4%) has surpassed urban coverage (44.3%).
- 2025 तक ग्रामीण कवरेज (47.4%) शहरी कवरेज (44.3%) से अधिक हो गया है।
- This growth is largely driven by government-sponsored schemes.
- यह वृद्धि मुख्य रूप से सरकारी योजनाओं के कारण हुई है।
- In rural India, government schemes covered 45.5% of the population in 2025, compared to 12.9% in 2017–18.
- ग्रामीण भारत में 2025 में सरकारी योजनाओं ने 45.5% आबादी को कवर किया, जो 2017–18 में 12.9% था।
- In urban areas, coverage by government schemes increased to 31.8% from 8.9%.
- शहरी क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं का कवरेज 8.9% से बढ़कर 31.8% हो गया।
- The average out-of-pocket expenditure per hospitalisation (excluding childbirth) was ₹34,064 in 2025.

- 2025 में अस्पताल में भर्ती (प्रसव को छोड़कर) प्रति मामले औसत जेब खर्च ₹34,064 था।
- India ranks as the 10th largest insurance market globally by premium volume (Swiss Re Report).
- स्विस् री रिपोर्ट के अनुसार भारत प्रीमियम के आधार पर विश्व का 10वां सबसे बड़ा बीमा बाजार है।
- FDI limit in insurance has been increased to 100% under the Insurance Laws (Amendment) Act, 2025.
- बीमा क्षेत्र में FDI सीमा को Insurance Laws (Amendment) Act, 2025 के तहत 100% कर दिया गया है।
- Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana has recorded 26.88 crore enrolments and 10.45 lakh claims disbursed (as of Feb 2026).
- प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में फरवरी 2026 तक 26.88 करोड़ नामांकन और 10.45 लाख दावों का निपटान हुआ है।
- Removal of 18% GST on premiums helps reduce cost and increase insurance penetration.
- प्रीमियम पर 18% GST हटाने से लागत कम होती है और बीमा का प्रसार बढ़ता है।

Ques: Why did the National Stock Exchange (NSE) sell around 1% stake in the Indian Gas Exchange (IGX)?

प्रश्न: नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) ने इंडियन गैस एक्सचेंज (IGX) में लगभग 1% हिस्सेदारी क्यों बेची?

- A) To raise capital / पूंजी जुटाने के लिए
- B) To comply with regulatory requirements / नियामकीय आवश्यकताओं का पालन करने के लिए
- C) Due to financial losses / वित्तीय नुकसान के कारण
- D) To exit the gas market / गैस बाजार से बाहर निकलने के लिए
- E) Due to merger with another exchange / अन्य एक्सचेंज के साथ विलय के कारण

Answer: Option B

Explanation | व्याख्या:

- The National Stock Exchange (NSE) sold around 1% stake in the Indian Gas Exchange (IGX).
- नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) ने इंडियन गैस एक्सचेंज (IGX) में लगभग 1% हिस्सेदारी बेची।
- The sale was done to comply with regulations set by the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (PNGRB).
- यह बिक्री पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड (PNGRB) के नियमों का पालन करने के लिए की गई।
- PNGRB rules state that no entity can hold more than 25% stake in IGX.
- PNGRB के नियमों के अनुसार कोई भी संस्था IGX में 25% से अधिक हिस्सेदारी नहीं रख सकती।
- NSE earlier held a 26% stake in IGX, which it had acquired in 2021.
- NSE के पास पहले IGX में 26% हिस्सेदारी थी, जो उसने 2021 में खरीदी थी।
- IGX is India's first online natural gas trading platform.
- IGX भारत का पहला ऑनलाइन प्राकृतिक गैस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है।
- It enables buying and selling of natural gas in a transparent manner.
- यह प्राकृतिक गैस की खरीद-बिक्री को पारदर्शी तरीके से संभव बनाता है।

Static Part | स्थैतिक जानकारी:

- National Stock Exchange (NSE) is a leading stock exchange in India.
- नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) भारत का प्रमुख स्टॉक एक्सचेंज है।
- Founded – 27 November 1992
- स्थापना – 27 नवंबर 1992
- Headquarters – Mumbai, Maharashtra
- मुख्यालय – मुंबई, महाराष्ट्र
- PNGRB – Petroleum and Natural Gas Regulatory Board regulates downstream oil and gas sector.
- PNGRB – पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड तेल और गैस क्षेत्र को नियंत्रित करता है।

Ques: Fintech company One MobiKwik Systems has received RBI approval to operate as which type of financial entity?

प्रश्न: फिनटेक कंपनी One MobiKwik Systems को RBI से किस प्रकार की वित्तीय संस्था के रूप में कार्य करने की मंजूरी मिली है?

- A) Small Finance Bank / स्मॉल फाइनेंस बैंक
- B) Payment Bank / पेमेंट बैंक
- C) Non-Banking Financial Company (NBFC) / गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी
- D) Cooperative Bank / सहकारी बैंक
- E) Insurance Company / बीमा कंपनी

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

- Fintech company One MobiKwik Systems has received approval from the Reserve Bank of India (RBI).
 - फिनटेक कंपनी One MobiKwik Systems को भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) से मंजूरी मिली है।
 - The approval allows it to operate as a Non-Banking Financial Company (NBFC).
 - यह मंजूरी इसे गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (NBFC) के रूप में कार्य करने की अनुमति देती है।
 - With this, the company can start its lending business.
 - इसके साथ कंपनी अपना ऋण (लेंडिंग) व्यवसाय शुरू कर सकती है।
 - MobiKwik will launch its lending arm named Mobikwik Financial Services.
 - MobiKwik अपनी लेंडिंग इकाई 'Mobikwik Financial Services' शुरू करेगी।
-

Ques: Mission SAKSHAM launched by RBI is primarily aimed at which sector?

प्रश्न: RBI द्वारा लॉन्च किया गया मिशन सक्षम मुख्य रूप से किस क्षेत्र के लिए है?

- A) Commercial Banks / वाणिज्यिक बैंक
- B) Rural Banks / ग्रामीण बैंक
- C) Urban Co-operative Banks / शहरी सहकारी बैंक
- D) NBFCs / गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां
- E) Payment Banks / पेमेंट बैंक

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

- Reserve Bank of India Governor Sanjay Malhotra launched Mission SAKSHAM on April 28, 2026.
- RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा ने 28 अप्रैल 2026 को मिशन सक्षम लॉन्च किया।
- Mission SAKSHAM (Sahkari Bank Kshamta Nirman) is a nationwide capacity-building initiative for Urban Co-operative Banks (UCBs).
- मिशन सक्षम (सहकारी बैंक क्षमता निर्माण) शहरी सहकारी बैंकों (UCBs) के लिए एक राष्ट्रव्यापी क्षमता निर्माण पहल है।
- RBI will conduct training programmes (in-person and e-learning) covering around 1.40 lakh participants including board members, senior management, and IT staff.
- RBI लगभग 1.40 लाख प्रतिभागियों (बोर्ड सदस्य, वरिष्ठ प्रबंधन, IT कर्मचारी आदि) के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करेगा।
- The programmes will also be delivered in regional languages to ensure wider accessibility.
- कार्यक्रम क्षेत्रीय भाषाओं में भी उपलब्ध होंगे, जिससे अधिक लोगों तक पहुंच सुनिश्चित होगी।
- The mission was designed in consultation with UCB umbrella organisations and cooperative federations.
- यह मिशन UCB के अम्ब्रेला संगठनों और सहकारी महासंघों के साथ परामर्श करके तैयार किया गया है।
- It was first announced in the Monetary Policy Statement on February 6, 2026.

- इसे पहली बार 6 फरवरी 2026 की मौद्रिक नीति में घोषित किया गया था।
- The aim is to improve governance, compliance culture, and institutional strength in the UCB sector.
- इसका उद्देश्य UCB क्षेत्र में शासन, अनुपालन संस्कृति और संस्थागत मजबूती को बढ़ाना है।
- There are over 1,400 UCBs in India serving urban and semi-urban populations and promoting financial inclusion.
- भारत में 1,400 से अधिक UCBs कार्यरत हैं, जो शहरी और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देते हैं।

Static Part | स्थैतिक जानकारी:

- Mission — SAKSHAM (Sahkari Bank Kshamta Nirman)
- मिशन — सक्षम (सहकारी बैंक क्षमता निर्माण)
- Meaning — “To make capable/competent”
- अर्थ — “सक्षम बनाना”
- Launch Date — April 28, 2026
- लॉन्च तिथि — 28 अप्रैल 2026
- Target Sector — Urban Co-operative Banks (UCBs)
- लक्ष्य क्षेत्र — शहरी सहकारी बैंक (UCBs)
- Total Participants — 1.40 lakh
- कुल प्रतिभागी — 1.40 लाख
- Training Mode — In-person + E-learning
- प्रशिक्षण मोड — प्रत्यक्ष + ई-लर्निंग
- Total UCBs — 1,400+
- कुल UCBs — 1,400+

Ques: Flipkart, Axis Bank, and PayU have introduced biometric authentication for card payments, replacing which traditional system?

प्रश्न: Flipkart, Axis Bank और PayU ने कार्ड पेमेंट के लिए बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन शुरू किया है, जो किस पारंपरिक प्रणाली को प्रतिस्थापित करता है?

- A) PIN / पिन
- B) OTP (One-Time Password) / ओटीपी
- C) CVV / सीवीवी
- D) Net Banking Password / नेट बैंकिंग पासवर्ड
- E) UPI PIN / यूपीआई पिन

Answer: Option B

Explanation | व्याख्या:

- Flipkart, Axis Bank, and PayU have jointly introduced biometric authentication for card payments.
 - Flipkart, Axis Bank और PayU ने मिलकर कार्ड पेमेंट के लिए बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन शुरू किया है।
 - Axis Bank cardholders can now approve payments using fingerprint or Face ID.
 - Axis Bank के कार्डधारक अब फिंगरप्रिंट या फेस आईडी के माध्यम से भुगतान को स्वीकृत कर सकते हैं।
 - This system replaces the traditional OTP (One-Time Password) method.
 - यह प्रणाली पारंपरिक OTP (वन-टाइम पासवर्ड) विधि को प्रतिस्थापित करती है।
 - PayU manages the payment infrastructure for this system.
 - इस प्रणाली के लिए PayU पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रबंधन करता है।
 - Wibmo, a subsidiary of PayU, handles the authentication process.
 - PayU की सहायक कंपनी Wibmo ऑथेंटिकेशन प्रक्रिया को संभालती है।
 - This move enhances security and improves user convenience in digital payments.
 - यह कदम डिजिटल भुगतान में सुरक्षा और उपयोगकर्ता सुविधा को बढ़ाता है।
-

Ques: RBI has set what time limit to classify a borrower as a wilful defaulter after NPA tagging?

प्रश्न: RBI ने NPA घोषित होने के बाद किसी उधारकर्ता को विलफुल डिफॉल्टर घोषित

करने के लिए कितनी समय सीमा तय की है?

- A) 3 months / 3 महीने
- B) 6 months / 6 महीने
- C) 9 months / 9 महीने
- D) 12 months / 12 महीने
- E) 18 months / 18 महीने

Answer: Option B

Explanation | व्याख्या:

- Reserve Bank of India (RBI) has introduced a timeline for classifying wilful defaulters.
- भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने विलफुल डिफॉल्टर घोषित करने के लिए समयसीमा निर्धारित की है।
- Banks must complete the process within 6 months of an account being classified as NPA.
- बैंकों को खाते के NPA घोषित होने के 6 महीने के भीतर प्रक्रिया पूरी करनी होगी।
- The process begins if a wilful default is observed during internal preliminary screening.
- यह प्रक्रिया तब शुरू होती है जब आंतरिक प्रारंभिक जांच में विलफुल डिफॉल्ट पाया जाता है।
- The rule ensures timely identification and action against wilful defaulters.
- यह नियम विलफुल डिफॉल्टर की समय पर पहचान और कार्रवाई सुनिश्चित करता है।
- The new guideline will come into effect from April 1, 2027.
- यह नया नियम 1 अप्रैल 2027 से लागू होगा।
- It aims to strengthen credit discipline and banking transparency.
- इसका उद्देश्य क्रेडिट अनुशासन और बैंकिंग पारदर्शिता को मजबूत करना है।

Ques: India's factory output is measured by which index?

प्रश्न: भारत में फैक्ट्री उत्पादन किस सूचकांक द्वारा मापा जाता है?

- A) Consumer Price Index (CPI) / उपभोक्ता मूल्य सूचकांक
- B) Wholesale Price Index (WPI) / थोक मूल्य सूचकांक
- C) Purchasing Managers' Index (PMI) / परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स
- D) GDP Deflator / जीडीपी डिफ्लेटर
- E) Index of Industrial Production (IIP) / औद्योगिक उत्पादन सूचकांक

Answer: Option E

Explanation | व्याख्या:

- India's industrial output growth slowed to a five-month low of 4.1% in March 2026.
- मार्च 2026 में भारत की औद्योगिक उत्पादन वृद्धि घटकर 4.1% रह गई, जो पांच महीने का न्यूनतम स्तर है।
- Factory output in India is measured by the Index of Industrial Production (IIP).
- भारत में फैक्ट्री उत्पादन को औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (IIP) द्वारा मापा जाता है।
- The growth for February 2026 was revised to 5.1% from the earlier estimate of 5.2%.
- फरवरी 2026 की वृद्धि दर को 5.2% से संशोधित कर 5.1% किया गया।
- The data is released by the National Statistics Office (NSO).
- यह आंकड़े राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) द्वारा जारी किए जाते हैं।

Ques: Which organization has been recognised as the PaRRVA agency by SEBI?

प्रश्न: SEBI द्वारा PaRRVA एजेंसी के रूप में किस संगठन को मान्यता दी गई है?

- A) National Stock Exchange of India (NSE) / नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया

- B) Bombay Stock Exchange (BSE) / बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज
- C) CARE Ratings Limited / केयर रेटिंग्स लिमिटेड
- D) CRISIL Limited / क्रिसिल लिमिटेड
- E) ICRA Limited / आईसीआरए लिमिटेड

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

- The Securities and Exchange Board of India (SEBI) has operationalised PaRRVA (Past Risk and Return Verification Agency).
- भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने PaRRVA (Past Risk and Return Verification Agency) को संचालन में ला दिया है।
- CARE Ratings Limited has been recognised as the PaRRVA agency.
- CARE Ratings Limited को PaRRVA एजेंसी के रूप में मान्यता दी गई है।
- National Stock Exchange of India (NSE) will function as the PaRRVA Data Centre (PDC).
- नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया (NSE) PaRRVA डेटा सेंटर (PDC) के रूप में कार्य करेगा।
- The initiative aims to improve transparency, credibility, and investor protection in financial markets.
- इस पहल का उद्देश्य वित्तीय बाजारों में पारदर्शिता, विश्वसनीयता और निवेशक सुरक्षा बढ़ाना है।
- The pilot phase began in December 2025, and full operations start from 4 May 2026.
- इसका पायलट चरण दिसंबर 2025 में शुरू हुआ और नियमित संचालन 4 मई 2026 से शुरू होगा।
- It enables investment advisors, research analysts, and algo trading firms to display verified performance records.
- यह निवेश सलाहकारों, रिसर्च एनालिस्ट्स और एल्गो ट्रेडिंग सेवा प्रदाताओं को सत्यापित प्रदर्शन रिकॉर्ड दिखाने में मदद करता है।

Static Part | स्थैतिक जानकारी:

- Securities and Exchange Board of India (SEBI) – Regulator of securities market
- भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) – प्रतिभूति बाजार का नियामक
- Established – 1988
- स्थापना – 1988
- Statutory Status – 1992
- वैधानिक दर्जा – 1992
- Headquarters – Mumbai
- मुख्यालय – मुंबई
- National Stock Exchange of India (NSE) – Established 1992
- नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया (NSE) – स्थापना 1992

Ques: NITI Aayog's "Digital Public Infrastructure (DPI) @2047" roadmap primarily focuses on which immediate phase of India's digital transformation?

प्रश्न: नीति आयोग का "डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर (DPI) @2047" रोडमैप भारत के डिजिटल परिवर्तन के किस तात्कालिक चरण पर मुख्य रूप से केंद्रित है?

- A) DPI 1.0 (2015–2025)
- B) DPI 2.0 (2025–2035)
- C) DPI 3.0 (2035–2047)
- D) AI 1.0 Phase
- E) BharatNet Phase III

Answer: Option B

Explanation | व्याख्या:

- NITI Aayog launched the "Digital Public Infrastructure (DPI) @2047" roadmap to achieve the vision of Viksit Bharat 2047.
- नीति आयोग ने विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए "डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर (DPI) @2047" रोडमैप लॉन्च किया।
- The roadmap was unveiled by Suman Bery and Ajay Kumar Sood.

- इस रोडमैप का अनावरण सुमन बेरी और अजय कुमार सूद द्वारा किया गया।
- India aims to become a \$30 trillion economy with a per capita income of \$18,000 by 2047 under the Viksit Bharat vision.
- विकसित भारत के तहत भारत का लक्ष्य 2047 तक \$30 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था और \$18,000 प्रति व्यक्ति आय हासिल करना है।
- DPI initiatives are already contributing nearly 1% to GDP and may reach 4% by 2030.
- DPI पहले वर्तमान में GDP में लगभग 1% योगदान दे रही हैं और 2030 तक 4% तक पहुंच सकती हैं।
- The roadmap has been developed by NITI Frontier Tech Hub in partnership with EkStep Foundation and Deloitte.
- यह रोडमैप नीति फ्रंटियर टेक हब द्वारा एकस्टेप फाउंडेशन और डेलॉइट के सहयोग से विकसित किया गया है।

- **It outlines two phases:**

DPI 2.0 (2025–2035): Focused on livelihood-led growth at scale

DPI 3.0 (2035–2047): Focused on broad-based prosperity

- इसमें दो चरण शामिल हैं:

DPI 2.0 (2025–2035): बड़े पैमाने पर आजीविका-आधारित विकास

DPI 3.0 (2035–2047): व्यापक समृद्धि सुनिश्चित करना

- The immediate focus is on DPI 2.0, which includes eight sectoral transformations.
- वर्तमान में ध्यान DPI 2.0 पर है, जिसमें आठ क्षेत्रीय परिवर्तन शामिल हैं।

Static Part | स्थैतिक जानकारी:

- NITI Aayog Established – 2015
- नीति आयोग की स्थापना – 2015
- Chairperson – Prime Minister of India
- अध्यक्ष – भारत के प्रधानमंत्री
- Headquarters – New Delhi
- मुख्यालय – नई दिल्ली
- DPI Full Form – Digital Public Infrastructure

- DPI का पूर्ण रूप – डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर

Ques: Under RBI's revised calamity loan framework, banks must invoke resolution plans within how many days of disaster declaration?

प्रश्न: RBI के संशोधित आपदा ऋण ढांचे के तहत बैंक को आपदा घोषणा के कितने दिनों के भीतर समाधान योजना शुरू करनी होगी?

- A) 30 Days / 30 दिन
- B) 45 Days / 45 दिन
- C) 60 Days / 60 दिन
- D) 90 Days / 90 दिन
- E) 135 Days / 135 दिन

Answer: Option B

Explanation | व्याख्या:

- The Reserve Bank of India (RBI) has revised its loan restructuring framework for borrowers affected by natural disasters.
- भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित उधारकर्ताओं के लिए ऋण पुनर्गठन ढांचे में संशोधन किया है।
- Under the new rules, banks must invoke the resolution plan within 45 days of disaster declaration.
- नए नियमों के अनुसार बैंकों को आपदा घोषणा के 45 दिनों के भीतर समाधान योजना शुरू करनी होगी।
- The implementation of the restructuring plan must be completed within 135 days.
- पुनर्गठन योजना को 135 दिनों के भीतर लागू करना आवश्यक है।
- Banks can now proactively initiate restructuring without waiting for borrower requests.
- अब बैंक उधारकर्ताओं के आवेदन का इंतजार किए बिना स्वतः पुनर्गठन प्रक्रिया शुरू

कर सकते हैं।

- Eligible borrowers must have standard accounts with no default exceeding 30 days at the time of disaster.
- पात्र उधारकर्ताओं के खाते स्टैंडर्ड होने चाहिए और आपदा के समय 30 दिन से अधिक डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए।
- Accounts turning NPA during the process can be upgraded back to standard after successful restructuring.
- इस अवधि में NPA बने खातों को सफल पुनर्गठन के बाद फिर से स्टैंडर्ड श्रेणी में अपग्रेड किया जा सकता है।
- Banks may also waive fees and charges for up to one year in eligible cases.
- पात्र मामलों में बैंक एक वर्ष तक शुल्क और चार्ज माफ कर सकते हैं।

Ques: EPFO's newly launched E-PRAAPTI portal is mainly designed for what purpose?

प्रश्न: EPFO द्वारा लॉन्च किया गया E-PRAAPTI पोर्टल मुख्य रूप से किस उद्देश्य के लिए बनाया गया है?

- A) To open new PF accounts / नए PF खाते खोलने के लिए
- B) To track and activate inoperative EPF accounts / निष्क्रिय EPF खातों को ट्रैक और सक्रिय करने के लिए
- C) To issue pension cards / पेंशन कार्ड जारी करने के लिए
- D) To provide loans / ऋण प्रदान करने के लिए
- E) To issue debit cards / डेबिट कार्ड जारी करने के लिए

Answer: Option B

Explanation | व्याख्या:

- The Employees' Provident Fund Organisation (EPFO) is launching the E-

PRAAPTI portal for members with old or inactive EPF accounts.

- कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) पुराने या निष्क्रिय EPF खातों वाले सदस्यों के लिए E-PRAAPTI पोर्टल लॉन्च कर रहा है।

- The portal helps users identify, track, link UAN, and activate inoperative EPF accounts.

- यह पोर्टल पुराने EPF खातों की पहचान, ट्रैकिंग, UAN लिंकिंग और सक्रियण में मदद करता है।

- Members can access accounts through Aadhaar-based authentication, even without a UAN.

- सदस्य आधार आधारित प्रमाणीकरण के माध्यम से बिना UAN के भी खातों तक पहुंच सकते हैं।

- An EPF account becomes inoperative if no contribution is made for 36 months (3 years).

- यदि 36 महीने (3 वर्ष) तक कोई योगदान नहीं होता है, तो EPF खाता निष्क्रिय हो जाता है।

- For members above 55 years, accounts become inoperative 3 years after retirement or age 55, whichever is later.

- 55 वर्ष से अधिक आयु के सदस्यों के लिए खाता सेवानिवृत्ति या 55 वर्ष की आयु (जो बाद में हो) के 3 वर्ष बाद निष्क्रिय हो जाता है।

- If a member is below 55 years, the account continues earning interest till 58 years even without contributions.

- यदि सदस्य 55 वर्ष से कम है, तो बिना योगदान के भी खाता 58 वर्ष की आयु तक ब्याज अर्जित करता रहता है।

- After 7 years, unclaimed balances are transferred to the Senior Citizens' Welfare Fund (SCWF).

- 7 वर्ष बाद दावा न की गई राशि Senior Citizens' Welfare Fund (SCWF) में ट्रांसफर कर दी जाती है।

- EPFO settled a record 8.31 crore claims in FY 2025–26.

- EPFO ने वित्त वर्ष 2025–26 में रिकॉर्ड 8.31 करोड़ दावों का निपटान किया।

Static Part | स्थैतिक जानकारी:

- Employees' Provident Fund Organisation (EPFO) – Social security organisation

- कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) – सामाजिक सुरक्षा संगठन

- Established – 1952
- स्थापना – 1952
- Headquarters – New Delhi
- मुख्यालय – नई दिल्ली
- Parent Ministry – Ministry of Labour and Employment
- संबंधित मंत्रालय – श्रम एवं रोजगार मंत्रालय
- UAN Full Form – Universal Account Number
- UAN का पूरा नाम – यूनिवर्सल अकाउंट नंबर
- Senior Citizens' Welfare Fund (SCWF) – Established 2016
- वरिष्ठ नागरिक कल्याण कोष (SCWF) – स्थापना 2016

Ques: Under RBI's new Type-I NBFC framework, what is the maximum asset limit for exemption?

प्रश्न: RBI के नए Type-I NBFC फ्रेमवर्क के तहत छूट के लिए अधिकतम एसेट सीमा कितनी है?

- A) ₹500 Crore / ₹500 करोड़
- B) ₹750 Crore / ₹750 करोड़
- C) ₹1,000 Crore / ₹1,000 करोड़
- D) ₹1,500 Crore / ₹1,500 करोड़
- E) ₹2,000 Crore / ₹2,000 करोड़

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

- The Reserve Bank of India (RBI) has introduced a new Type-I NBFC framework for small NBFCs.
- भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने छोटे NBFCs के लिए नया Type-I फ्रेमवर्क पेश किया है।
- Under this framework, NBFCs with total assets below ₹1,000 crore are eligible for exemption.

- इस फ्रेमवर्क के तहत ₹1,000 करोड़ से कम एसेट वाले NBFCs छूट के पात्र होंगे।
- Eligible NBFCs must not accept public funds and should have no direct customer interface.
- पात्र NBFCs पब्लिक फंड स्वीकार नहीं करेंगे और उनका ग्राहकों से सीधा संपर्क नहीं होना चाहिए।
- Such entities will be exempted from registration and reserve fund requirements under the RBI Act, 1934.
- ऐसे संस्थानों को RBI अधिनियम, 1934 के तहत रजिस्ट्रेशन और रिजर्व फंड नियमों से छूट मिलेगी।
- Existing NBFCs can apply for deregistration through the PRAVAAH portal by 31 December 2026.
- पात्र NBFCs 31 दिसंबर 2026 तक PRAVAAH पोर्टल के माध्यम से डी-रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन कर सकते हैं।
- The board must pass an annual resolution confirming compliance with the framework.
- प्रत्येक वर्ष बोर्ड को नियमों के पालन की पुष्टि करते हुए प्रस्ताव पारित करना होगा।

